

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 304 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 13, 2001/कार्तिक 22, 1923

No. 304]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 13, 2001/KARTIKA 22, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

जांच शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2001

**विषय :** भारत में सिंगापुर और ईरान से विनाइल एसिटेट मोनोमर के आयातों के संबंध में पाटनरोधी - च आरम्भ करना

सं. 58/1/2001-डी जी ए डी.— मै0 वाम आर्गेनिक केमिकल्स लि0, नौएडा, जिनका सयत्र गजराँला, उ0 प्र0 और नीरा जिला पुण म द न 1995 म यथासशाधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुआ को पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम 1995 क अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जि० १) जिसम इसकें बाद प्राधिकारी कहा गया है) क संमक्ष याचिका दायर की है जिसम सिंगापुर और ईरान क मूल क अथवा वहा से निर्यातित विनाइल एसिटेट मानामर क पाटन का आराप लगाया गया है तः21

पाटनरोधी जाच करने और पाटनरोधी शुल्क लगान का अनुराध किया गया है

**शामिल उत्पाद:**

2 वतमान याचिका म शामिल उत्पाद विनाइल एसिटेट मानामर क (जि० १) इत्यक्त (इरान से आयात

वस्तु कहा गया है) विनाइल एसिटेट मानामर एक कार्बनिक यौगिक क (जि० १) इत्यक्त (इरान से आयात

मानोमर एक पारदर्शक रंगहीन द्रव्य है । इसका रासायनिक सूत्र सी 4 एच 6 एन ओ 2 है । इसका इस्तमाल पोलिमर्स, जल पर आधारित पेंट्स, एडहैसिव, पंपर कोटिंग और इमल्शन पोलिमराइजेशन प्रोसेस के उत्पाद में किया जाता है । विनाइल एसिडेट मोनामर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची 1 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप शीर्ष 291532 के तहत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सक्तात्मक है और यह वर्तमान जाच के दायर पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है

### घरेलू उद्योग

3 यह याचिका में 0 वाम आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, नॉएडा द्वारा दायर की गई है याचिकाकर्ता के अलावा विनाइल एसिडेट मोनामर भारत में एक दूसरी कंपनी अर्थात् में 0 विनाइल कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा भी उत्पादित किया जाता है तथापि में 0 विनाइल कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड सबद्ध वस्तु का एक आयातक है याचिकाकर्ता द्वारा सबद्ध वस्तु का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है और याचिकाकर्ता उपरोक्त नियमों के नियम 5 (3)(क) के अनुसार याचिका दायर करने के आधार सबधी मापदंड को पूरा करता है

### शामिल देश

4 वर्तमान जाच में शामिल देश सिंगापुर और इंडोनेशिया हैं (जिन्हें इसके बाद सबद्ध देश कहा गया है) ।

**समान वस्तु**

5 याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया है कि उसका द्वारा उत्पादित माल सिंगापुर और ईरान के मूल के या वहां से निर्यातित माल के समान वस्तु है इसलिए वर्तमान जांच के प्रयाजन से याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित माल का उपरोक्त नियम के अर्थ के भीतर सबद्ध देश से आयातित माल के 'समान वस्तु' माना जा रहा है

**सामान्य मूल्य**

6 याचिकाकर्त्ताओं ने उल्लेख किया है कि एक प्रतिष्ठित दैनिक आई एम आई एस - एल आर में प्रदर्शित कीमत संबंधित वस्तु की प्रचलित कीमता का संकेत है और दैनिक में प्रदर्शित कीमतों पर विचार करते हुए सिंगापुर में उत्पादक अपनी उत्पादन लागत वसूल नहीं कर रहे हैं इस प्रकार, याचिकाकर्त्ता ने सिंगापुर के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा प्रशासनिक बिक्री लागत और लाभ के लिए उचित अभिवृद्धि के साथ परिकल्पित उत्पादन लागत के आधार पर किया है याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि ईरान एक गरीब बाजार अर्थव्यवस्था है और इसलिए उन्होंने ईरान से निर्यात के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं 44/99-सी शू (एन टी) दिनांक 15 जुलाई, 1999 और अधिसूचना सं 28/2001, दिनांक 31 मई, 2001 की शर्तों के अनुसार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है -

"गरीब-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से कीमत अथवा परिकल्पित लागत के आधार पर अथवा

किंवा एस तीसरा दश म भारत समत अन्य दशा क लिए कीमत आधार पर किया जाएगा अथवा जहा यह संभव न हो वहा सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ मार्जिन यदि आवश्यक हो, का शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन करके समान वस्तु हेतु भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत समत किंवा अन्य उचित आधार पर किया जाएगा।

भारत सरकार की उक्त अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ आगे यह दिया गया है कि -

इस पैराग्राफ की टिप्पणी के अनुसार गर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला दश शब्दों से तात्पर्य एस प्रत्येक दश में जो उक्त टिप्पणी में सूचीबद्ध है और इसमें ऐसा कोई भी दश शामिल है जिसका निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्धारण करते हैं और जो दश, लागत और कीमत निर्धारण संबंधी ढाँचे के बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं करता है जिससे एस दश में वस्तुओं की बिक्री से उक्त वस्तु के उचित मूल्य का पता नहीं चलता है। ऐसा निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करेंगे कि क्या -

(क) कोई वस्तु या सेवा समत, भारत में वास्तव में निविष्टियाँ प्राप्त की जाती हैं या नहीं।

(ख) निविष्टि बिक्री या एवं निवेश के बारे में एस दश की संबंधित फर्मों का निर्णय बाजारी सकता हो आपूर्ति एवं मांग प्रदर्शित करते हैं, के अनुरूप और इस बारे में पर्याप्त सरकारी वस्तुओं के बिना लिया जाता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत से बाजार मूल्य

में कोई अंतर है।

- (ii) एसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन है जो पूर्ववर्ती गर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली खासकर परिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास, अन्य बट्टे खाता, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋण की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के कारण आई हैं,
- (iii) एसी फर्म दिवालियापन और सम्पत्ति संवर्धन ऐस कानूनों के अधीन हैं जो फर्म के प्रचालन से कानूनी निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी प्रदान करते हैं, और
- (iv) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है

उक्त अधिसूचनाओं में आगे कहा गया है कि कोई देश जो यह स्थापित करने की इच्छा रखता है कि वह ऊपर दिए गए मानदण्डों के अनुसार एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है तो उस वह सभी आवश्यक सूचना प्रस्तुत करनी होगी जिस निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने ईरान के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और एक उचित लाभ मार्जिन का शामिल करके यथा समायोजित उत्पादन लागत के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित उत्पादन की परिकल्पित लागत के आधार पर किया है

### निर्यात कीमत

7 याचिकाकर्ता ने आकड़ों के गोण खाने के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है कागखाना स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए भाड़, बोमा, कमीशन, अंतर्देशीय परिवहन तथा बंदरगाह पर खर्च के लिए समायोजन का दावा किया है

### पाटन मार्जिन

8. इस बात का प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निर्यात निर्यात कीमत से बहुत अधिक है, जिससे इस बात का प्रथम दृष्ट्या संकेत मिलता है कि निर्यातकों द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

### क्षति

9. क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंड जैसे बाजार हिस्से में गिरावट, बिक्री में गिरावट, बिक्री वसूली में गिरावट, संबद्ध वस्तु की बिक्री से उचित कीमत न मिलने से घरेलू उद्योग का हुई हानि में वृद्धि, परिष्कृत वस्तुओं के भंडार का निर्माण समग्र तथा सचयी रूप से प्रथम दृष्ट्या यह बताता है कि घरेलू उद्योग का पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

### पाटनरोधी जांच का आरंभ

10. उपराक्त पराग्राफों का दखत हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।

### जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2001 से 30 सितम्बर, 2001 तक की है ।

### सूचना देना

12. इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले सबद्ध दश के निर्यातका और भारत के आयातका का अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी भारत सरकार, पाटनराधी तथा संबद्ध शुल्क निदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110011 को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

### समय-सीमा

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जा उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिख गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी इस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रख गए हैं।

यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना ज़रूरत से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करता है या तदुत्तरण देग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्या के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा कन्द्रीय सरकार का यथोचित सिफारिश कर सकता है।

एल. बी. सप्तर्षि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2001

**Subject : Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Vinyl Acetate Monomer from Singapore and Iran into India**

**No. 58/1/2001-DGAD.—** M/s. Vam Organic Chemicals limited, Noida having their plants at Gajraula, UP and Nira, district Pune, have filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Vinyl Acetate Monomer originating in or exported from Singapore and Iran and requested for Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

### PRODUCT INVOLVED

2. The product involved in the present petition is Vinyl Acetate Monomer (hereinafter referred as subject goods). Vinyl Acetate Monomer is an organic compound. Vinyl Acetate Monomer is a clear colourless liquid. Its chemical formula is  $C_4H_6NO_2$ . It is used for production of Polymers, water-based paints, adhesives, paper coating and emulsion polymerization process. Vinyl Acetate Monomer is classified under Chapter 29 of schedule 1 of the Customs Tariff Act under sub heading 291532. This Custom classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

### DOMESTIC INDUSTRY

3. The petition has been filed by M/s. Vam Organic Chemicals limited, Noida. Besides the petitioner, Vinyl Acetate Monomer is produced in India by another company viz. M/s. Vinyl Chemicals (India) Limited. However, M/s Vinyl Chemicals (India) Limited is an importer of the subject goods. The production of subject goods by the petitioner constitutes a major proportion of the total domestic production. Therefore, the petitioner represents the domestic industry and the petitioner satisfies the criteria of standing to file the petition in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.



**COUNTRY INVOLVED**

4. The countries involved in the present investigation are Singapore and Iran(hereinafter referred to as the subject countries).

**LIKE ARTICLE**

5. The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods produced, originating in or exported from Singapore and Iran. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like articles' to that imported from the subject countries within the meaning of the Rules supra

**NORMAL VALUE**

6. The petitioners have stated that the prices reflected in a reputed journal ICIS-LOR are indicative of the prevailing prices of subject goods and considering the prices reflected in the journal, the producers in Singapore are not recovering their cost of production. Therefore, the petitioner has claimed the normal value in respect of Singapore on the basis of constructed cost of production with reasonable addition for administrative, selling cost and for profits. Petitioner has claimed that Iran is a non-market economy and, therefore, they have claimed Normal Value in respect of exports from Iran in terms of Government of India, Ministry of Finance Notifications No. 44/99-CUS(NT) dated 15<sup>th</sup> July, 1999 and Notification No. 28/2001 dated 31<sup>st</sup> May, 2001 which inter alia state that

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin."*

The provisions of the aforesaid Government of India Notifications further stipulate inter alia that:

The term "non market economy country" subject to the Note to this paragraph means every country listed in that note and includes any country which the designated authority determines and which does not operate on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise. While making such determination, the designated authority shall consider as to whether,

- (i) the decision of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State

interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

- (ii) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- (iii) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and
- (iv) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

The Notifications further state that any country seeking to establish that it is a market economy country as per criteria enunciated above, may provide all necessary information which shall be taken due account by the designated authority. Therefore, the petitioner has claimed Normal value in respect of Iran on the basis of constructed cost of production determined on the best information available with regard to cost of production duly adjusted to include selling, general and administrative expenses and a reasonable profit margin.

### **EXPORT PRICE**

7. The petitioner has claimed the export price on the basis of secondary source information. Adjustments have been claimed on account of freight, insurance, commission, inland transportation, port expenses to arrive at the Export Price at ex-factory level.

### **DUMPING MARGIN**

8. There is sufficient prima-facie evidence that Normal Value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the net export price indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

### **INJURY AND CAUSAL LINK**

9. Various parameters relating to injury such as the decline in market share, decline in sales, decline in the sales realisation, increase in losses of the Domestic Industry due to inability to realize fair and reasonable price from sale of the subject goods, building up of inventory of finished goods prima-facie indicate collectively and cumulatively that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping.

## **INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATIONS**

10. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

## **PERIOD OF INVESTIGATION (POI)**

11. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1<sup>st</sup> April 2001 to 30<sup>th</sup> September 2001.

## **SUBMISSION OF INFORMATION**

12. The exporters in the subject country and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

## **TIME LIMIT**

13. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

## **INSPECTION OF PUBLIC FILE**

14. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

